औद्योगिक गलियारे के लिए खरीदी जाएगी 25 हजार हेक्टेयर जमीन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक गलियारा (आईएमएलसी) परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों से जमीन क्रय और अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि आईएमएलसी के विकास के लिए 27 स्थानों पर भूमि खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। पहले से चिह्नित 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में से लगभग 85 प्रतिशत जमीन आपसी सहमति

27 स्थानों पर चल रही है भूमि खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया

से खरीदी जा चुकी है। बची हुई जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे अधिकाधिक जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजे जाएं। वहीं, सभी जिलों के नोडल अपर जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे नए लक्ष्य के मुताबिक अपने-अपने जिलों में जमीन चिह्नित कर इसी सप्ताह यूपीडा को प्रारंभिक प्रस्ताव सौंपें, ताकि तकनीकी टीम से परीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।

मुख्य सचिव के निर्देश पर आईएमएलसी के विस्तार के लिए 25 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिह्नित कर खरीदने और अधिग्रहित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पुराने जिलों के साथ नए जिलों से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिन जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें लखनऊ, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और मुजफ्फरनगर शामिल है। इसके अलावा निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे शामली, बिजनौर, बरेली, सीतापुर, रामपुर, कासगंज, सहारनपुर, बागपत और हाथरस को भी जोड़ा गया है।

दरअसल, आईएमएलसी को एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां हरित पट्टियां, चौड़ी आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, निर्बाध बिजली-पानी आपूर्ति, बेहतर जल निकासी और उपयोगिता नेटवर्क की व्यवस्था की जाएगी।